

फर्द अहकाम

बेबीकार

बनाम राम डिगान व कमा

नाम न्यायालय

केस संख्या 10/2019

न्यायालय उपख
मु.न. 10/2019

1. बरीत

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विवृत रूप में
	6/7/22	व. फ. उपो मुन्वकिल गव का की रिपोर्ट पत्रांक 1956 दि. 29.6.22 से उपरि 50 की गई है जो शामिल पत्रावली क्रि. 100 पत्रावली वाली मजिस्ट्रेट आदेशात्राट दिनांक 28/07/22 को पेश है। 882
	28/7/22	व. फ. उपो पत्रावली वाले अन्तिम आदेशात्राट दिनांक 23/08/22 को पेश है। 882
	3/8/22	पत्रावली पेश हुई मुन्वकिल ग. पत्रावली को दि. 3/8/22 उपो अपिलान्ट की अपील स्वीकार की जा रही है निष्पत्ति पत्र से लिखा जाकर शामिल पत्रावली क्रि. 100 पत्रावली क्रि. 100 शामिल होकर देवी नमक से नम होकर दाखल कर दी है। 882



गायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर
मु.न. 10/2019

उनवान

1. बंशीधर पुत्र गोपीराम जाति मीणा, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

—अपीलार्थी—

बनाम

1. रामकिशन पुत्र स्व० महादेव
2. रामवतार पुत्र स्व० महादेव
समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत उदयपुरिया जरिये सरपंच ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थागण/रेस्पोडेन्ट्स—

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश 25.10.78
सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया, तहसील चौमूँ बाबत नामान्तकरण संख्या 367 दिनांकित
25.1.78 ग्राम उदयपुरिया का अनुचित अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम
तस्दीक करने।

निर्णय दिनांक 03.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर साबिक खसरा नम्बर 900, 901 कुल किता 2 का कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1705 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1706 रकबा 0.61 हैक्टेयर, 1706/1 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर सम्पूर्ण का रिकार्ड खातेदार काश्तकार अपीलार्थी भू राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आया हैं, अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजीयात को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.7.66 को तत्कालीन खातेदार महादेव पुत्र हुक्मा व कन्हैयालाल पुत्र झंथा, जाति मीणा, निवासी ग्राम उदयपुरिया से क्रय कर खातेदार काश्तकार हैं, जिस भूमि को अपीलान्त द्वारा बांटे पर काश्त करने हेतु भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को दी गई, जिसमें संवत् 2025 के पश्चात् उक्त आराजी को काश्त हेतु रेस्पोडेन्ट के पूर्वाहक अधिकारी स्व० महादेव को दी गई, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के पूर्वाधिकारी स्व० महादेव द्वारा उक्त आराजीयात का अवैध व फर्जी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर, पटवारी हल्का तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया से साजकर अनुचित व अवैध रूप से दिनांक 25-10-78 को अपने पुत्रों रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से नामान्तकरण संख्या 367 तस्दीक करवाकर उसका राजस्व अभिलेखों में अमल

88
उप खण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

दरामद करवा लिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्त की ओर से यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. आदेश अधीन अपील तथ्यों रिकार्ड एवं न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं।
2. अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने वास्तविक स्थिति को समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्री एवं कान्ट्रेरी टू लॉ अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय हैं।
3. अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने हस्तगत नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्त को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान न कर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है, इसलिए आदेश निरस्तनीय हैं।
4. नामान्तकरण भरने से पूर्व न तो पटवारी हल्का ने विक्रय पत्र की जाँच की, न ही तहकीकात की तथाकथित जो दस्तावेज अधीनस्थ अदालत में प्रस्तुत हुआ वह फर्जी व कूटरचित दस्तावेज हैं, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के उल्लंघन में किसी दीगर को खड़ा करके कराया गया है, जिसके विरुद्ध भी सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है। जिसकी कानून में कोई अहमियत भी नहीं है, जिस पर गौर न कर अधीनस्थ अदालत ने भयंकर कानूनी भूल की है।
5. अपीलाधीन आदेश के रिकार्ड के अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्त मीना जाति का सदस्य है, जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है तथा रेस्पोजेन्ट की जाति रैगर है, जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं, अपीलान्त उक्त भूमि का कानूनन धारा 42 आर.टी.एक्ट 1955 के उल्लंघन में हस्तान्तरण नहीं कर सकता है, न ही ऐसा करना सही है, जिस सम्बन्ध में सम्बन्धित भू-निरीक्षक द्वारा भी प्रश्नगत नामान्तकरण पर रिपोर्ट भी की गई है, जिसके बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से कानून के विपरीत जाकर आदेश अधीन अपील पारित कर अमल दरामद गलत किया है, जो निरस्तनीय हैं।
6. अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण तस्दीक करने सम्बन्धी लेण्ड रेवन्यू रूल्स के अल्स 121 (4) की कतई पालना न कर अनुचित व अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय हैं।
7. उक्त आराजी का अपीलान्त खातेदार काबिज काश्तकार है, जिसके द्वारा कोई हस्तान्तरण पत्र रेस्पोजेन्ट जो वरवक्त नाबालिग थे के हित में नहीं कराया नहीं ऐसा कानूनन हो सकता, न ही कानून में ऐसे किसी दस्तावेज की कोई अहमियत है, जिस ओर ध्यान न देकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ ग्राम पंचायत के सरपंच ने बिना कोरम की स्वीकृति के गलत रूप से किया है, जो निरस्तनीय हैं।
8. अपीलाधीन आदेश कानूनन आदेश की परिभाषा में न आने से निरस्तनीय हैं।

उप ⁸⁸⁸खण्ड अधिकारी
चौम जिला-जयपुर

9. अपीलधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपीलान्त को किसी भी प्रकार से सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान न कर रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 2 से साजकर अपीलधीन नामान्तकरण तरदीक किया है, अपीलान्त प्रशनगत आराजीयात का खातोदार काशतकार है, अपीलधीन नामान्तकरण अनुधित व अवैध रूप से रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम तरदीक किया गया है, अपीलधीन आदेश दिनांक 25.10.78 बावत नामान्तकरण संख्या 367 ग्राम उदयपुरिया से अपीलान्त के अधिकारों पर फुठाराघात हुआ है तथा नामान्तकरण से व्यथित है जिसको सुना जाना प्रार्थनीय है।

10. अपीलधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने आदेश दिनांक 25-10-78 बावत नामान्तकरण संख्या 367 पारित करने से पूर्व किसी भी प्रकार से सूचना व सुनवाई का अवसर अपीलान्त को प्रदान नहीं किया है, न ही नामान्तकरण अधीन अपील से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण भरने से पूर्व पटवारी हल्का ने कोई सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है, रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत से साजकर गलत रूप से, अवैध व कानून के विरुद्ध नामान्तकरण तरदीक करवाया है, जिसका ज्ञान अपीलान्त को पूर्व में नहीं था, न ही होने दिया, अपीलान्त ने तथाकथित विकय पत्र दिनांकित 20.12.1972 के बावत एक सिविल वाद सिविल जज एवं न्यायिक मजि० चौमूँ, जिला जयपुर के यहां प्रस्तुत करने पर उक्त सिविल मुकदमा में रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने पर अपीलान्त के अधिवक्ता द्वारा उक्त जवाब के सम्वन्ध अपीलान्त से चर्चा करने पर अपीलधीन नामान्तकरण की जानकारी करने बावत अपीलान्त पटवारी हल्का के पास दिनांक 6.6.2017 को गया व रिकार्ड के विषय में जानकारी चाही तो पटवारी हल्का ने अपीलान्त की भूमि रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तकरण दर्ज होना बताया व नकल मांगने पर जमाबन्दी की नकल देकर नामान्तकरण की नकल तहसील से लेने हेतु कहा, जिस पर अपीलान्त दिनांक 7.6.2017 को अपने वकील श्री हीरालाल सैनी एड० से मुगालत व जानकारी करवाकर नामान्तकरण की नकल के लिये आवेदन किया जिस पर नकल दिनांक 8.6.2017 को दी गई, नकल मिलने पर अपीलधीन आदेश का पूर्ण ज्ञान हुआ है, इससे पूर्व नामान्तकरण का ज्ञान अपीलान्त को किसी भी स्रोत से नहीं हुआ, अपीलधीन आदेश जानकारी से अन्दर मयाद है, जो दो रूपयों के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है, अपीलधीन आदेश अवैध व क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर गलत रूप से पारित किया है, जिसको चेलेंच करने के लिये मयाद का विन्दू बाधक भी नहीं है तथा मयाद माफी प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। 882

उप खण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला-जयपुर

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.78 बाबत नामान्तकरण संख्या 367 ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर को निरस्त किये जाने का आदेश फरमायें ।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स ने प्रारम्भिक आपत्ति एवं जवाब बाबत अपील अन्तर्गत धारा 76 एल0आर0एक्ट 1956 पेश कर निवेदन किया है कि अपील के प्रथम पैरा में की यह इबारत की ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के साबिक खसरा नम्बर 900, 901 कुल किता 2 का कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1705 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1706 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1706/1 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर सम्पूर्ण का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलार्थी भू राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आया हैं, अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजीयात को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28-7-66 को तत्कालीन खातेदार महादेव पुत्र हुक्मा व कन्हैयालाल पुत्र झंथा, जाति मीणा, निवासी ग्राम उदयपुरिया से कय कर खातेदार काश्तकार हैं अपीलान्त स्वयं साबित करें। उपरोक्त वर्णित भूमियों के दिनांक 20.12.1972 से मालिक काबिज स्वामी रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 हैं। अपीलान्त द्वारा अपील के प्रथम पैरा में वर्णित भूमि बेचान के बाद अपीलान्त का प्रथम पैरा में वर्णित भूमियों बाबत कोई कब्जा काश्त हक अधिकार नहीं रहा व उक्त भूमियों रेस्पोंडेन्ट्स के कब्जे काश्त व खातेदारी में हैं। अपीलान्त का कोई 21 स्वामित्व निहित नहीं है व विक्रय पत्र दिनांक 20.12.72 के बाद कोई हक अधिकार व स्वामित्व अपीलान्त का प्रथम पैरा में वर्णित भूमियों बाबत नहीं रहा। अपीलान्त की ओर से अपील के प्रथम पैरा में वर्णित यह तथ्य की विवादित आराजीयात को काश्त करने हेतु बांटे पर समय-समय पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को दी गई, अपीलान्त स्वयं साबित करें, क्योंकि अपीलान्त ने अपने प्रथम पैरा में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया की अपीलान्त ने प्रथम पैरा में वर्णित भूमियों को किन-किन व्यक्तियों को बांटे पर दी व किस व्यक्ति को कब से कब तक दी। शेष इबारत गलत होने से अस्वीकार हैं। अपीलान्त ने या अपीलान्त की ओर से किसी ने भी महादेव को कभी भी प्रथम पैरा में वर्णित भूमियों को बंटायत पर नहीं दी, बल्कि महादेव रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 का पिता जरिये मालिक, स्वामी संरक्षक खरीद की दिनांक से उक्त भूमियों पर काबिज काश्त खातेदार था व बालिक होने पर स्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हैं व निरन्तर काश्त कर रहे हैं, 10-12 पेड़ लगा रखे हैं चारो तरफ तारबन्दी कर रखी है व उक्त प्रथम पैरा में वर्णित भूमियों के पास ही स्थित अन्य भूमि में स्थित चाह से अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाइनों के जरिये फसलो की पिलाई सिंचाई करते हैं व उत्पादन प्राप्त करते आ रहे हैं व लगान सरकारी अदा करते आ रहे हैं। सन् 1972 के बाद प्रथम पैरा में वर्णित भूमि अपीलान्त के स्वामित्व व खुदकाश्त की कतई नहीं रही, ना ही ऐसा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। अपीलान्त ने जानते हुये गलत तथ्य अपील में अंकित किये हैं व सही तथ्य छिपाये है, सही तथ्य विशेष विवरण में दर्ज हैं। अपीलान्त ने उस दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया, जिसे फर्जी, कुटर्चित बताया गया है, जबकि नामान्तकरण संख्या 367 जिस आधार पर खुला उसका इन्द्राज नामान्तकरण में है, जो स्वयं अपीलान्त की सहमति से खुला हैं।

प्रश्नगत नामान्तकरण अपीलान्त द्वारा तस्दीक करवायें गये विक्रय पत्र के आधार पर बाद जांच कब्जा खोला गया जो कतई प्राकृतिक न्यायशस्त्र के विरुद्ध नहीं हैं। प्रश्नगत नामान्तकरण अपीलान्त द्वारा स्वयं मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर तस्दीक करवाये गये विक्रय पत्र व मौके पर कब्जे काश्त की जांच के आधार पर खोला गया और अगर विक्रय पत्र अपीलान्त के स्थान पर किसी दीगर व्यक्ति को खड़ा करके तस्दीक करवाया गया तो अपीलान्त ने रेस्पोंडेन्ट्स के

विरुद्ध कोई फौजदारी प्रकरण क्यों नहीं दर्ज करवाया इसका कोई कारण उल्लेखित नहीं किया गया, जहाँ तक सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही के विचारधीन होने का प्रश्न है तो यह सही है कि अपीलान्ट ने विक्रय पत्र दिनांकित 20.12.72 को चुनौती दे रखी है, जिस वाद में पक्षकारों के अधिकार तय होने की विक्रय पत्र फर्जी, कूटस्थित है या स्वयं अपीलान्ट ने तरदीक करवाया, यहाँ तक की अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुरती व स्थायी निषेधाज्ञा का मय अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक चौमू में पेश किया, जिसमें से वाद अभी लम्बित हैं व टी.आई. प्रार्थना पत्र पर वाद के अन्तिम निर्णय तक उक्त नामान्तकरण से सम्बन्धित भूमियों बाबत यथार्थिति बनाये रखने के आदेश प्रभावी है, जिन तथ्यों को अपीलान्ट ने छिपाया है एवं उक्त टी.आई. में पारित आदेश के विपरीत आदेश श्रीमान् को मुगालते में रखकर पारित करवाना चाहते हैं। जबकि विधि का स्पष्ट सिद्धान्त है की जहाँ कोई वाद पक्षकारों के अधिकारों बाबत विचारधीन हो वहाँ सामग्री कार्यवाहियों में कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये। यह कि अपील का मद नम्बर 5 जिस प्रकार व जिस अनुक्रम में लिखा गया है, गलत होने से अस्वीकार है, जो तथ्य मद नम्बर 5 में अंकित किये गये है वे वाद साक्ष्य ही साक्ष्य न्यायालयों में लम्बित वादों में तय हो सकते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से विधि से सम्बन्धित प्रश्न है, जो कि अपील में तय नहीं किये जा सकते हैं।

ग्राम पंचायत ने विधि अनुसार नामान्तकरण तरदीक किया है। अपीलान्ट कर्ताई नामान्तकरणस संख्या 367 से सम्बन्धित भूमियों का खातोदार काबिज काश्तकार नहीं हैं। विक्रय पत्र दिनांकित 20.12.72 स्वयं अपीलान्ट ने मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर तरदीक करवाया है, जिसे अपीलान्ट ने प्रश्नगत करते हुये नियमित वाद सक्षम न्यायालय में पेश कर रखे है, जिनके लम्बित रहते हस्तगत अपील में कोई आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

नामान्तकरण संख्या 367 अपीलान्ट द्वारा तरदीक करवाये गये विक्रय पत्र के आधार पर वाद जांच कब्जा खोला गया। जहा तक रेस्पोंडेन्टस संख्या 1 व 2 से साज करने का प्रश्न है तो नामान्तकरण संख्या 367 के समय रेस्पोंडेन्टस संख्या 1 व 2 नाबालिक थे, साज करने का प्रश्न ही नहीं है। अपीलान्ट ने कहीं रेस्पोंडेन्टस के पिता द्वारा साज करना अंकित किया है, कहीं रेस्पोंडेन्टस द्वारा जो कि गलत है।

अपीलान्ट ने बिना किसी आधार के तथ्यों को बार-बार दोहराते हुये अपील गलत आधारों पर पेश की है, अपीलान्ट ने मद नम्बर 11 में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद का जवाब रेस्पोंडेन्टस द्वारा प्रस्तुत करने के वाद चर्चा करने पर नामान्तकरण बाबत जानकारी होने के तथ्य अंकित करते हुये नामान्तकरण की जानकारी होना अंकित किया, जबकि राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत वाद में दिनांक 2-3-16 को ही विक्रय पत्र एवं लगान की रसीदे पेश कर उक्त बाबत अवगत करवा दिया था, जिन तथ्यों को छिपाकर अपीलान्ट ने गलत रूप से नियमित वाद लम्बित होते हुये अपील पेश की है, जो खारिज योग्य हैं।

अपीलान्ट ने हस्तगत अपील नामान्तकरण संख्या 367 ग्राम उदयपुरिया तहसील चौयूँ को इस आधार पर चुनौती देते हुये प्रस्तुत की है की विक्रय पत्र दिनांकित 20.12.1972 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता महादेव ने किसी वंशीधर नामक व्यक्ति को अपीलान्ट के स्थान पर खड़ा करके अपीलान्ट की सहमति व जानकारी के बिना विधि विरुद्ध रूप से तरदीक करवाया, जिसके आधार पर प्रश्नगत नामान्तकरण अपीलान्ट को सूचना दिये बिना, बिना सुने विधि विरुद्ध रूप से खोला गया। जिस सम्बन्ध में स्पष्ट करना आवश्यक है की अपीलान्ट ने विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1972 को निरस्त किये जाने बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में वाद, वाद संख्या 81/16 प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें दिनांक 22.12.2016 को रेस्पोंडेन्टस संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं के विधिक व तथ्य सम्बन्धी आधारों पर जवाब दावा पेश किया गया। उक्त वाद में अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक चौमू

882
उप खण्ड अफिसर
चौमू जिला

जिला जयपुर के समक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 2.3.16 को विक्रय पत्र की फोटो प्रति रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत करने पर विक्रय पत्र की जानकारी होना अंकित किया, जबकि हस्तगत अपील में उक्त सिविल वाद मु०नं० 81/16 में रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब से जानकारी प्राप्त होना, रिकार्ड प्राप्त करना बातया जो स्पष्ट करता है की अपीलान्ट ने विरोधाभाषी व मिथ्या तथ्य उक्त विक्रय पत्र, नामान्तकरण एवं उस सम्बन्ध में जानकारी बाबत अंकित किये हैं, जो स्पष्ट करते है की अपीलान्ट ने ही विक्रय पत्र तस्दीक करवाया एवं नामान्तकरण खुलवाया, जिसके करीब 40-45 वर्षों बाद मियाद बाहर हस्तगत अपील पेश की है, उक्त सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है की जहाँ किसी हित बाबत किसी कार्य व अस्तित्व में आये दस्तावेज की जानकारी किसी व्यक्ति को हो तो वह उसे मियाद अवधि में ही प्रश्नगत कर सकता है, जो कि उक्त तथ्य साक्ष्य से ही सक्षम न्यायालय द्वारा वाद में ही बाद साक्ष्य तय किया जा सकता है और वाद सक्षम न्यायालये में लम्बित है, जिस कारण अपील खारिज योग्य हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है की जब अपीलान्ट ने स्वयं विक्रय पत्र तस्दीक करवाया, जिससे अपीलान्ट इंकार करता है जो तथ्य भी साक्ष्य का विषय है, जिसके साक्ष्य द्वारा साबित हो जाने पर क्या अपीलान्ट को कोई हक अधिकार अपील में वर्णित भूमियों बाबत प्राप्त होंगे या उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित होगी यह तथ्य भी साक्ष्य का विषय है, अपील में उक्त तथ्यों बाबत निर्णय नहीं किया जा सकता है। जिस कारण भी अपील खारिज योग्य हैं।

अतः प्रारम्भिक आपत्ति मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील को उक्त आधारों पर खारिज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 367 दिनांक 25.10.78 को दर्ज करने पर पटवार हल्का द्वारा दर्ज उपरान्त गिरदावर हल्का द्वारा नामान्तकरण अवैध माना जाकर अपील में भेजा जाने की टिप्पणी अंकित की गई है न ही उक्त विक्रय पत्र अपीलान्ट के द्वारा करवाया गया है। हस्तगत नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा न ही तहकीकात की तथाकथित दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के उल्लंघन में किसी दीगर व्यक्ति को खडा करके करवाया गया है। नामान्तकरण तस्दीक करते समय लैण्ड रेवेन्यु रूल्स के अल्स 121(4) की कतई पालना न कर अनुचित व अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट की स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमानों की कृपा करें। साथ में अधिवक्ता अपीलान्ट के द्वारा न्यायीक दृष्टान्त RRD 1992 रामकुंवार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं राज्य सरकार का परिपत्र वित्तकर विभाग का आदेश दिनांक 03.12.2021 पेश किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स को बार बार लिखित बहस पेश करने हेतु समय दिया गया। उसके बावजूद भी अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने न ही लिखित बहस पेश की न ही मौखिक बहस कर कथन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। हस्तगत अपील में न्यायालय का यह अभिमत है कि प्रश्नगत विवादित भूमि अभिलिखित खातेदार काश्तकार की जाति मीणा के नाम अंकित रही है तथा रेस्पोंडेन्ट्स 1 व 2 के द्वारा जरिये विक्रय पत्र करना बताया गया है। अपीलान्ट की जाति मीणा अनुसुचित जनजाति के अन्तर्गत आती है तथा रेस्पोंडेन्ट्स रैगर जाति का व्यक्ति है। जो अनुसुचित जाति के अन्तर्गत आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी धारा 46 (क) तथा धारा 49 (क) के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा अपने सैं भिन्न जाति के व्यक्ति के पक्ष में अपनी कृषि भूमि के विक्रय, वसीयत, दान करने पट्टे या उष

उप खण्ड
चौम जिला

र पट्टे देने तथा विनिमय करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत न्यायीक दृष्टान्त RRD 1992 रामकुंवार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं राज्य सरकार एवं राज्य सरकार का परिपत्र वित्तकर विभाग का आदेश दिनांक 03.12.2021 पूर्ण रूप से हस्तगत प्रकरण में चर्चा होते है। जिससे अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 367 दिनांक 25.10.1978 वाके ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं निरस्त करने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 367 दिनांक 25.10.1978 निरस्त किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इस आधार पर किए गए समस्त पश्चातवर्ती अंकन शून्य व बेअसर घोषित किए जाते है। इस आशय का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। तदनुसार पालना हेतु तहसीलदार तहसील चौमूं को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

४४
उप सीमा खेतान अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर